08-02-2023 General Budget (2023-24)-General Discussion(not concluded) BUDGET (GENERAL) Gogoi, Shri Gaurav Dubey, Dr. Nishikant Gogoi, Shri Gaurav Dubey, Dr. Nishikant Tagore, Shri Manicka Gogoi, Shri Gaurav Chaudhary, Shri P.P. Meghwal, Shri Arjun Ram Chaudhary, Shri P.P. Baalu, Thiru Thalikkottai Rajuthevar Mahtab, Shri Bhartruhari Enquiry Committee Higher Education Per Capita Income Price Stabilization Social Welfare Food Security Farmers' Welfare Digital Library Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) Government Schemes Social Security Schemes Capial Expenditure Scheme(CAPEX)

le: Union Budget (2023-24)-General Discussion

ननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई ।

गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बहुत-सी चुनौतियां हैं ।? (व्यवधान) आज हमारे देश संख्या लगभग 140 करोड़ की है ।? (व्यवधान)

सर, आप हाउस को ऑर्डर में लाइए ।? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : आप दो मिनट के लिए रुक जाइए ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, बैठिए ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, विराजें ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं नाम से पुकारूंगा । जिन्हें बैठना है, बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : इधर के माननीय सदस्यगण भी बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी ।

? (व्यवधान)

गौरव गोगोई: सर, आप हाउस को ऑर्डर में लाइए ।? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, बैठिए ।

? (व्यवधान)

ननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी ।

गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, आज हमारे देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं । सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या लगभग 140 करोड़ को पार कर चुकी है । बहुत लोग यह कहते हैं कि अब चीन से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है । इस वजूद भी आज बेरोजगारी की जो दर है, यह लगभग 7 प्रतिशत है । सी.एम.आई.ई. की ओर से जनवरी में यह आंकड़ा आया पिछले महीने यह 8 प्रतिशत था ।

23 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair)*

आप देख सकते हैं कि आज हमारा देश कितनी कठिन परिस्थिति में है । एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, दूस फ बेरोजगारी बढ़ रही है । इसके साथ ही साथ हम देखें कि कोविड और विभिन्न कारणों के पश्चात् आज गरीबी भी बढ़ रही करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ रहा है । 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री अनाज देना पड़ रह र बेरोजगारी की दर 7 प्रतिशत है तो हमारे देश में आज कितनी गम्भीर चुनौतियां हैं, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं ।

इंफ्लेशन की जो बात है तो आज ही आरबीआई ने 25 बेसिस प्वायंट्स रेट को दोबारा बढ़ाया क्योंकि इंफ्लेशन जित ना चाहिए, उतना घट नहीं रहा है । हमने आज यह देखा कि दिसम्बर के महीने में कोर इंफ्लेशन 6.1 प्रतिशत था और आ रबीआई के द्वारा यह अंदाजा लगाया गया है कि for the Financial Year, 2023-24, core inflation will still be at 5.3 t, which is still quite high. Retail inflation is at 5.72 per cent, which is still on the higher side.

आज जनसंख्या की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और इस थ ही साथ आज हमारे सीमांचल पर हमारे उत्तर और पूर्व की तरफ चीन की ओर से एक नई चुनौती दिख रही है । ऐसे वक्त चाहते थे कि एक ऐसा बजट आए, जो वर्तमान की चुनौतियों को संभालने के लिए देश को एक नई दिशा दे ।

लेकिन, हमने यह देखा कि इस बजट में जो चुनौतियां हैं, उसके लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है ।

सर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो बॉण्ड्स को देखकर विभिन्न प्रकार की रेटिंग देती हैं । मैं भी इस बजट को ग देना चाहूंगा । इस बजट को मैं ?ए? रेटिंग देता हूं । परंतु, यहां ?ए? वह वाला ?ए? नहीं जो हमको स्कूल की परीक्षा में मिल यह ?ए? सिर्फ अडाणी का है । इस बजट में जो भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं हैं, Budget at a glance में जहाँ आपको बजट हज ार करोड़ रुपये का दिखाई देगा, सबके पीछे आपको अडाणी का फायदा दिखायी देगा और यह हो रहा है ।

सर, पिछले तीन-चार वर्षों के बजट में यही हो रहा है । दलाल स्ट्रीट पर अडाणी जैसा जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए ट बहुत अच्छा बजट है । जो गरीब, बेरोजगार और मध्यम वर्ग है, जो साधारण लोग हैं, उनके लिए यह बजट कोई मायने न ता है ।

सर, इस बजट में यह क्या बोलते हैं? इनका जो सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड है, जिस पर यह बहुत गर्व महसूस करते हैं । लते हैं कि हमने कैपेक्स बढ़ाया । सरकार ने अपने खर्चे के द्वारा, आज हमने 10 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स दिया । आप एक्सपेंडिचर लगभग 45 लाख करोड़ रुपये है । उसमें से आपका जो कैपेक्स है, वह 10 लाख करोड़ रुपये है । इसको ले बहुत वाहवाही करते हैं । ऐसा लगता है कि इससे ही पूरी बेरोजगारी कम हो जाएगी ।

सर, हमने क्या देखा? इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपये कैपेक्स था । आपको याद होगा, पिछले साल 7 लाख कैपेक्स थ से पहले 5 लाख कैपेक्स था । उससे पहले 3 लाख कैपेक्स था । नतीजा क्या है? बेरोजगारी अभी भी आठ प्रतिशत पर है का नतीजा है कि आज भी लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए हैं । इसका नतीजा है कि आज हम ह्यूमन डेवलप क्स में नीचे चलते जा रहे हैं । अगर आप बारीकी में जाएंगे तो इस बजट में कैपेक्स का जो बजट 10 लाख करोड़ रुपये मेंसे पांच लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट में जाता है । ट्रांसपोर्ट बोले तो हाइवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और रेलवेज है । अभी हमने ा? हाइवे का मतलब - अडाणी, पोर्ट का मतलब ? अडाणी, एयरपोर्ट का मतलब ? अडाणी । यही इनकी मंशा है कि सरक इवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और रेल बनाए और बाद में एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा ये सारे प्रोजेक्ट्स अडाणी को दिये जाएं । की मंशा है । हमने यही देखा है । यह कोई नई बात नहीं है । आज यह वाहवाही लेते हैं कि सरकार ने 10 लाख करोड़ रु र्च किये हैं । इसमें निजी क्षेत्र ने क्यों नहीं खर्च किया? प्राइवेट सेक्टर का इनवेस्टमेंट कहाँ है? ? (व्यवधान)

सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं ।? (व्यवधान)

NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I have a point of order.

ननीय सभापति: सॉरी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

? (व्यवधान)

R. NISHIKANT DUBEY: It is under rule 353. ? (*Interruptions*)

सर, माइक ऑन कीजिए । ? (व्यवधान)

गौरव गोगोई: सर, ऐसा बार-बार नहीं होना चाहिए । यदि आप एक बार एन्करेज करेंगे तो यह बार-बार होते जाएगा वधान)

सर, आप प्रेसिडेन्स देख लीजिए । यदि एक बार शुरू हो गया तो यह ट्रेंड रुकता नहीं है । अभी तो हमारी शुरुआत हुई ी अडाणी का नाम बहुत बार आएगा । निशिकांत जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए । अभी यह बहुत बार आने वाला है वधान)

सर, मैं पूरा भाषण बोल देता हूं । उसके बाद उनको जितनी भी आपति जतानी है, वह बाद में बोल देंगे ।? (व्यवधान)

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यह गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को इनवेस्ट नहीं क , उसके लिए इनकी रणनीति है ।? (व्यवधान)

ON. CHAIRPERSON: My advice would be, you can avoid specifically mentioning the name. That is my adv you.

RI GAURAV GOGOI: Thank you, Sir.

Now, may I continue?

ON. CHAIRPERSON: Yes.

गौरव गोगोई: ताकि, निजी क्षेत्र को इनवेस्ट नहीं करना पड़े, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाए और फिर एसेट मोनेटाइजे द्वारा, इन्होंने एक लंबी लिस्ट बनायी है, जिसमें नीति आयोग ने कहा है कि हम क्या-क्या एसेट मोनेटाइज करेंगे । यह स्टेट हा बेचेंगे, यह एक्सप्रेस वे को बेचेंगे, यह पावर ट्रांसमिशन को बेचेंगे, यह अर्बन बस टर्मिनल्स को बेचेंगे, यह वेयर हाउसेस ंगे, यह गैस पाइपलाइन को बेचेंगे और किसको बेचेंगे ? वह ?ए? रेटिंग है ।

सर, जो ?ए? बजट है न, उसी को बेचेंगे । अब तो आप खुश हैं । अब तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं । आप ?ए? कंपनी को बेचे

जो एसेट बनता है, वह पब्लिक मनी से बनता है । एसेट जो मॉनेटाइज होता है, वह क्रॉनी कैपिटलिज्म के द्वारा होता जानकारी भी जानना चाहेंगे कि आप पिछले तीन-चार सालों से कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेक्स बढ़ाये हैं ।? (व्यवधान)

ON. CHAIRPERSON: Let me read it out.

....(Interruptions)

निशिकांत दुबे : मॉनेटाइजेशन की हिंदी क्या है?

ON. CHAIRPERSON: When you are mentioning a name or making an allegation against any person, who is cessarily a Member of this House.

....(Interruptions)

RI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, he is not making any allegation.

ON. CHAIRPERSON: When you are mentioning a name, if that person is not a Member in the House, how c
defend himself?

....(Interruptions)

OF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, Adani is not the name of a person. It is the name of a company!
terruptions)

RI GAURAV GOGOI: Thank you, Sir. *....(Interruptions)* May I continue, Sir. *....(Interruptions)*

ON. CHAIRPERSON: First let him complete.

....(Interruptions)

ON. CHAIRPERSON: Prof. Roy, please sit down.

....(Interruptions)

ON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, please sit down.

....(Interruptions)

ON. CHAIRPERSON: The Speaker may at any time prohibit any Member from making any such allegation if
of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House.

....(Interruptions)

RI B. MANICKAM TAGORE: How is it derogatory to the dignity of the House? *....(Interruptions)*

ON. CHAIRPERSON: The Speaker has to take a decision.

....(Interruptions)

ON. CHAIRPERSON: Or, that no public interest is served by making such allegation. So, in that respect I ha
uested you not to mention the name.

....(Interruptions)

RI GAURAV GOGOI: Sir, with all due respect, मेरे जो भी आरोप हैं, वे सरकार पर हैं । मेरे अभी तक जो भी एलीगेशंस है
कार पर हैं । किसी निजी कंपनी पर आरोप नहीं है, आरोप सरकार पर है । आपकी जो एडवाइज़ है, परामर्श है, मैं उस
वूल करता हूं ।

ये जो कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, उसको लेकर कितनी जॉब्स बनीं, वेजेज़ कितने बढ़े, क्या इसका कोई आंकड़ा है? ट्रांसप
सबसे ज्यादा जो 5 लाख करोड़ रुपये बजट मिलता है, हमारे अश्वनी वैष्णव जी रेलवे विभाग के मंत्री हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसप
ट इनके विभाग को मिलता है । हम भी चाहते हैं कि रेलवे विभाग में बेरोजगारी कम हो ।

ननीय सभापति : इस बार मिला है । इस बार रेलवे को सबसे ज्यादा मिला है ।

गौरव गोगोई: सर, रेलवे विभाग में तीन लाख पदों पर कोई नहीं है । रेलवे विभाग में वैकेंसीज़ हैं । आप उनको भरिए । ज यह जानना चाहते हैं कि रेलवे में जो अलग-अलग रैक्स स्टोर्स में आएंगे, नये-नये कोचेज़ बनेंगे, इससे कितने नये रोज ी? इससे कितने नये रोजगार सृजित होंगे? ये सारे रोजगार क्या जो पहले की एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वहीं पर जाने वाले हैं? ारी चिंता है ।

सर, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गईं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी । ठीक है, हमें गर्व होता है, लेकिन गर्व थ हमें थोड़ी डिग्निटी और ह्युमिनिटी भी होनी चाहिए । आज हमारा मुकाबला किसके साथ है? अगर हम अर्थव्यवस्था की ं तो हमारा मुकाबला आज चीन के साथ है । चीन की जो पर-कैपिटा इंकम, जिसका जिक्र हमारे वित्त मंत्री ने अपने ब षण में किया था कि लगभग 1 लाख 90 हजार हमारी पर-कैपिटा इंकम है । चीन की पर-कैपिटा इंकम हमसे 6 गुना ज्यादा मेरिका की पर-कैपिटा इंकम हमसे 35 गुना ज्यादा है । हम भले ही फास्टेस्ट ग्रोइंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पर-कैपि म में देखें, तो 80 करोड़ लोगों को आज बिना मूल्य के जो अनाज मिल रहा है, वही हमारी सच्चाई है । कितना आगे हम ना है, यह हमको आज कबूल करना पड़ेगा, यह सच हमको कबूल करना पड़ेगा ।

आपने कैपेक्स का एक बजट बनाया, एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया । ठीक है, सरकार बोलती है कि हम ग्रोथ पर ध्य हैं, आरबीआई बोलती है कि हम इनफ्लेशन पर ध्यान देते हैं । मेरा प्रश्न है कि रोजगार पर कौन ध्यान देगा? रोजगार निर्धा ट कब बनायेंगे? When will we make a job-oriented Budget?

दूसरा, कैपेक्स के संबंध में मेरा कहना है कि कैपेक्स तो सरकार का बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज़ र देखेंगे तो उनका एक्सपेंडीचर फ्लैट है । पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज़ को और पैसा नहीं दिया जा रहा है । आप वर्ष 2021- एक्चुअल एक्सपेंडीचर देखें तो लगभग 4.37 लाख करोड़ रुपये पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज़ को दिया था और वर्ष 2023-24 ई देखें, तो जहां पहले वर्ष 2021-22 में एक्चुअल में 4.37 लाख करोड़ रुपये था, बीई वर्ष 2023-24 में 4.87 लाख करोड़ हो गय ारी जो पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं, उनको हम ताकत क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे इतने नवरत्न हैं, मिनी रत्न हैं, वहां पर बहुत ी स्किल्ड लोग काम करते हैं । हम वहां उनको क्यों नहीं और पैसे दे रहे हैं, उनका कैपेक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?

नार्थ ईस्ट में इलेक्ट्रीकल पॉवर कॉरपोरेशन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, कोचीन में शिपयार्ड है, इतने सारे लिस्ट हैं । आप ां भी पब्लिक सेक्टर के लिस्ट होंगे । आज उनको सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, वे सरकार विडेंड देते हैं लेकिन सरकार से कैपेक्स खर्च का पैसा उनको नहीं मिलता है ।

स्टेट को इन्होंने 50 साल के लिए लोन दिया है, इसे एक साल बढ़ाया है, लेकिन स्टेट्स आज भी जिस प्रकार से लोन यदा लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं सेंटर-स्टेट के बीच जैसा पहले डिस्कशन प्लानिंग कमिशन में होता था, ज नहीं होता है । सेंटर बस डिक्टेक्ट देती है, सेंटर बस इंस्ट्रक्शन देती है और स्टेट को मानना पड़ता है, लेकिन स्टेट्स के स म नहीं करती है ।

मैं दोबारा आरोप लगा रहा हूं, ये जो पूरा कैपेक्स है, एक विशेष ए कंपनी को फायदा दिलाने के लिए कैपेक्स की स्ट्रेटजी जॉब ओरिएंटेड नहीं है । दूसरी बात के लिए बहुत वाह-वाह लेते हैं कि हमने फिसिकल डेफिसिट के ग्लाइड पथ को मेन या है । वर्ष 2023-24 में इन्होंने फिसिकल डेफिसिट 5.9 रखा, पिछले साल 6.4 रखा, यह अच्छी बात है । फिसिकल डेफि इड पथ कन्सोलिडेट होनी चाहिए, लेकिन इसका बोझ इस बजट में किसने उठाया? इसका बोझ अगर किसी ने उठाया ब और मध्यम वर्ग ने उठाया । कैसे इन्होंने फिसिकल डेफिसिट को मेनटेन किया? उन्होंने फूड और फर्टिलाइजर पर ब्सिडी है, उसको इन्होंने घटाया । यूरिया सब्सिडी को घटाया, न्यूट्रिटेन्ट्स सब्सिडी को घटाया, एफसीआई के फूड सब्सिडी ा घटाया, नेशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट पर सब्सिडी को घटाया । वर्ष 2022-23 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 72 ह ोड़ रुपये की फूड सब्सिडी थी, आज वह घटकर 59 हजार करोड़ रुपये रह गई है । फूड सब्सिडी पहले एफसीआई को 22-23 आरई में 2. 1 लाख करोड़ रुपये थी वह आज घटकर 1.37 लाख करोड़ रुपये हो गयी है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको फिसिकल डेफिसिट मेनटेन करना है, इसका बोझ गरीब क्यों उठाए? इसका ब सान क्यों उठाए? इसका बोझ मजदूर क्यों उठाए? इनके जो करीबी दोस्त ए हैं, जिसका इन्होंने कर्ज माफ कर दिया, उन

वेश कहां है? आज हम देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री मोबाइल फोन, टीवी सेट्स और कनैक्टर्स के
ाते हैं, उनका कस्टम ड्यूटी घटा दिया, कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया । दो-तीन साल पहले कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत था,
22 प्रतिशत कर दिया । जब आपको रेवेन्यू मेन्टेन करना है तो आप अपने खर्च गरीब और सोशल सेक्टर पर खर्च कम क
र जब आपको अपने अमीर दोस्तों को फायदा देना है तब आपको फिसिकल डेफिसिट की याद नहीं आती, इससे कि
कसान हुआ? कॉरपोरेट टैक्स इन्होंने 30 से 22 प्रतिशत कर दिया, सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स कट से लगभग 1.80 लाख करोड़ रु
नुकसान हुआ । वर्ष 2019-20 में 86 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, वर्ष 2020-21 में 90 हजार करोड़ रुपये
कसान हुआ, यह कमेटी ऑन ऐस्टिमेट्स ने कहा है ।

टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है, इनसे टैक्स कलैक्ट नहीं किया जा रहा है । वर्ष 2020-21 में 18 लाख करोड़ रुपये एक्चु
र्ष था । आज बीई में सिर्फ 23.3 लाख करोड़ रुपये है, ये रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं । ये बार-बार अमीरों को रेवड़ी देते हैं
गरीबों को मदद करना हो तब इनको दर्द होता है । लेकिन जब अमीरों को मदद करना हो, सरचार्ज घटाना हो, तब इन
ड़ी दिखाई नहीं देता ।

आज सरचार्ज में क्या किया है? जिनका एनुअल इनकम 5 करोड़ रुपये से ज्यादा था, उस पर सरचार्ज 37 परसेंट था,
ाकर 25 परसेंट कर दिया । पहले एक अंतर होता था, जिनका एनुअल इनकम 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा
नों वर्गों के लिए अलग-अलग सरचार्ज रेट थे, आज इन्होंने दोनों को घटा दिया, क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर और फूड सब्सि
ाओ, दूध के दाम बढ़ाओ और अमीर दोस्तों के सरचार्ज कम करो, उनकी फैक्ट्रियों में इनपुट पर कस्टम ड्यूटी कम करो, अ
ी हो रहा है । आज हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है, लगभग जो 7 प्रति
एसटी है, It says ?64 per cent of GST is being contributed by the bottom 50 per cent of our country.?

आज यह सच्चाई है । विदेश का सबसे अमीर वर्ग का सिर्फ 10 प्रतिशत जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है जबकि हमारे यहां बॉ
परसेंट, जो गिर-गिर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गिर-गिर कर अस्पताल में जा रहे हैं, लगभग 64 परसेंट जीएसटी देते
ज इनको फ्यूल पर कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, इलैक्ट्रिसिटी पर कोई सहूलियत नहीं, कुकिंग गैस पर कोई सहूलियत न
ल रही है । 14 किलो का गैस सिलेंडर दिल्ली में लगभग हजार रुपये का हो गया है, गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर बढ़ ग
और ये अच्छे दिन की बात करते हैं । अच्छे दिन आए हैं तो अडानी के आए हैं और गरीबों के लिए सिर्फ बुरे दिन आए
गाई और बेरोजगारी आई है । ? (व्यवधान) सर, यह आरोप तो नहीं है । क्या यह आरोप है? ? (व्यवधान)

सर, गरीबों को क्या मिलता है? गरीबों को सिर्फ भाषण मिलता है । क्या-क्या सपने दिखाए थे? वर्ष 2022 में सबको घर मि
एगा, हाउसिंग फॉर ऑल । वर्ष 2022 में हम आ गए हैं, वर्ष 2022 में क्या हुआ? किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी,
एगी, 2022 तक स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी और गंगा नमामि गंगा हो जाएगी, लेकिन यह सब नहीं हुआ । यदि कुछ हुआ है
का दाम बढ़ा है ।

महोदय, ये किसानों की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं । सर, आपने तो ओडिशा में बहुत क्लाइमेट च
ा है । आप जानते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वर्षा पर पड़ता है । रेनफॉल का पैटर्न ब
ा है । जिस वक्त वर्षा होनी चाहिए, नहीं होती है और जिस वक्त नहीं होनी चाहिए, उस वक्त होती है । इसके कारण किस
फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है और इसलिए बाजार में उत्पाद का दाम बढ़ रहा है जो कि इनफलेशन से जुड़ा है । लग
प्रतिशत किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं, इन्होंने इस बजट में क्या किया? कृषि सिंचाई योजना के बजट को घटा दिया है ।
00 करोड़ रुपये इरीगेशन स्कीम का बजट है, जबकि पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का बजट था ।

महोदय, प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कही गई थी ताकि उचित मूल्य मिले । आज प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं है । टमा
ज, आलू के ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए 2014 करोड़ के बजट की घोषणा की गई थी, उसमें 50 प्रतिशत कम किया गया है
र्केट इन्टरवेंशन स्कीम नहीं है, एमएसपी लॉ का, कोई डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का कोई जिक्र नहीं है । एमएसपी गा
भी कोई जिक्र नहीं है । केसीसी लोन को लेकर आज किसानों की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि किसान केसीसी लोन
स नहीं कर पा रहे हैं । अगर मैं इस सरकार से गुहार लगाऊंगा तो यह लगाऊंगा कि जिस प्रकार से आपने बड़ी कंपनियों
न माफ किया, उसी तरह किसानों के केसीसी लोन माफ करें ।

महोदय, आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है? ये बोल रहे हैं कि हमने आवास योजना के लिए बजट बढ़ाया, उ
वन मिशन के लिए बजट बढ़ाया । ठीक है, इन्होंने दो योजनाओं का बजट बढ़ाया, लेकिन किसका बजट घटाया? एमजीनरे
बजट घटाया, ऐतिहासिक रूप से घटाया । क्या बोलते हैं? यह तो डिमांड बेस्ड है, जब डिमांड आएगी तब हम देंगे । अ
छले सालों के रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितनी डिमांड आती है । ये चाहते हैं कि बजट में कम रुपये दें और बाद में सप्लीमें
ट्स द्वारा ज्यादा रुपये बढ़ाएं । इस प्रक्रिया से क्या होता है? आप मेरी बात सुनिए, ओडिशा में भी यही समस्या है । बजट में क
ा दो और बाद में सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में पैसा बढ़ा दो, जब इस प्रकार से ये काम करते हैं तो क्या होता है? इससे मजदूर
य पर वेज नहीं मिलता है । मजदूर के पेंडिंग वेजेज़ बढ़ते जाते हैं, समय पर नहीं मिलते हैं । आज पेंडिंग वेजेज का अमा
ता जा रहा है । इस फाइनेंशियल ईयर में 690 करोड़ पेंडिंग वेजेज़ का अमाउंट ड्यू है । यह आज इनकी समस्या है
वधान)

महोदय, मैंने किसानों की बात कह दी और दूसरी बात महंगाई और बेरोजगारी के बारे में भी कह दी । अब मैं बात क
हता हूं कि हमारी सीमा पर जो चुनौती मंडराती हुई दिखाई दे रही है, और यह उत्तर में भी है और पूर्व में भी है । डिफेंस
ारी सेना सरकार से चाहती थी कि लगभग बजट में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हो, लेकिन आपने सिर्फ 13 प्रतिशत बढ़ोतरी की
पिटल आउटले 1.62 लाख करोड़ है और पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत हाइक नहीं है ।

आज वायु सेना तरस रहा है कि हमको 42 फ्लाइंग स्क्वाड्रन्स चाहिए । आज भी उनके पास 42 फ्लाइंग स्क्वाड्रन्स नहीं
ere is a shortage. नेवी चाहता है कि आईएनएस विक्रांत पर हवाई जहाज उतरे, लेकिन आज भी आईएनएस विक्रांत
इटर जेट नहीं उतर पा रहा है । पैसे की कमी है । आज सुखोई के लिए हमें अपने मशीन और एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड क
उसके लिए हमें पैसे चाहिए, लेकिन ये उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं । वे कैसे लड़ेंगे? जो चुनौती है, उस चुनौती के साथ वै
ंगे, चीनी चुनौती के साथ के कैसे लड़ेंगे?

सर, आप देखिए कि हमारी सरकार के विदेश मंत्री जी यह कहते हैं कि आज जो हमारा चीन के साथ संबंध है, वह प
ा नहीं है । पहले जैसा नहीं है तो हुआ क्या? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गुहार लगाऊंगा कि आप अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री
न कीजिए ।

सर, चाइना से इम्पोर्ट बढ़ता ही जा रहा है । वर्ष 2014 से चाइना से इम्पोर्ट बढ़ता ही जा रहा है । चाइना के साथ
फिसिट लगभग 36 बिलियन डॉलर था । वर्ष 2021 में वह लगभग 70 बिलियन डॉलर हो गया । इन्हीं के टाइम में वह दुगुना
ा है । हमारी सेना को क्या मैसेज जा रहा है? हम सेना को बोलते हैं आप सीमा पर जुटे रहिए, लड़ते रहिए और हम यहां-वह
ी समान खरीदते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं । सरकार के पास क्या नीति है? वे बोलते हैं कि मोबाइल फोन के पार्ट्स
डिसिन के जो एपीआईज आते हैं, वे चीन से आते हैं, इसीलिए हमारी चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है । यह आपने कैसा स्क
ाया है? आपने पीएलआई का कैसा स्कीम बनाया है, जहां हमारा भी विकास हो रहा है और हम अपने ही विकास से चीन का
कास कर रहे हैं । यह कैसा स्कीम है? आज पूरा देश, पूरी दुनिया चीन से अपनी सप्लाई चेन्स हटा रही है । आज दुनिया अप
न पर निर्भरता कम कर रही है और एक एकलौता देश, मोदी सरकार की जो नीति है, जो भारत की कमजोरी है, जो चीन
यात-निर्यात पर निर्भर है, वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है । इससे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है ।

आज चीन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव के साथ संबंध बढाए जा रहा है । आपने एमईए
ट में कितना इंटरनेशनल ऐड दिया? आपने कहीं किसी विदेशी सरकार को कुछ बसेज दे दिए तो उसको लेकर वाह-वाह
हैं । आज ऐसी नौबत आ गई है कि बस देते हुए हमारी सरकार को महसूस होता है कि हमने चीन की तुलना अपने पड़
ों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया है । इसलिए, हमें लगता है कि इनकी जो आँख है, उस आँख से वह ए रेटिंग बना
लिए ये बजट में ऐसा करते हैं ।

सर, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में क्या हो रहा है? अगर हमें चीन से मुकाबला करना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था
कतवर बनाना पड़ेगा । हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा । लेकिन, आज 12 प्रतिशत एक्सपोर्ट्स गिरे हैं । Over
wth in eight core sectors is only 9.8 per cent. This is not even close to the nominal growth. It is only 9.8 per ce
e growth rate in coal, refinery, steel, and cement is minimal. The contribution of manufacturing sector to Gr

lue Addition is only 17 per cent. This Government had the target of 25 per cent and we only have achieved 17 p
t. रुपये का वैल्यू कम हो गया । आप ही के प्रधान मंत्री जब मुख्य मंत्री थे तो बोलते थे कि जब रुपये का स्तर गिरता है तो दे
सम्मान भी गिरता है । जब पिछले साल एशिया में सबसे कमजोर करेंसी रुपया था, तब आपने क्या सोचा? तब भी आपके प
क सुविधा थी कि जो रुपया गिरते हुए नीचे आ रहा है, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को कंपटीशन मिलना चाहिए और एक्सपो
ने चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए । आपने उस प्रकार की ट्रेड, करेंसी और स्ट्रेटेजी नहीं बनाई । आपकी इस विफलत
2020 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि लगभग सवा पाँच करोड़ भारतवासी दोबारा गरीबी रेखा में वापस चले गए हैं । आज रि
डीपी कम हो चुकी है । वह धीरे-धीरे घट रही है । आज लोगों का अनुमान है कि वर्ष 2023-24 में जीडीपी 6.5 परसेंट रहेग
2022-23 में यह लगभग 7 परसेंट है ।

सर, ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं । जम्मू-कश्मीर में इंवेस्टमेंट कम हो चुका है । वर्ष 2017-18 में जम्मू-कश्मीर
वेश 840 करोड़ रुपये था । आज वर्ष 2021-22 में केवल 376 करोड़ रुपये है । वह आधा से कम हो गया है और ये जम्मू-कश्
बात करते है । धिक्कार है ऐसी नीति पर, जो ठंड के वर्ष में जम्मू-कश्मीर के लोगों को बुलडोजर से तोड़ रही है । धिक्कार
ी नीति पर जो रातों-रात एक राज्य को उस राज्य का दर्जा छीनकर उसको यू.टी. बना देती है और राज्य का दर्जा दिखाने
ए आज तक इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है ।

हमें देखना है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है । ऐसी नीति बनाइए, आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर ध्
ा चाहिए । आज गारमेन्ट्स में लेबर इम्प्लॉइड है, अपैरल्स में लेबर इम्प्लॉइड है, टेक्सटाइल्स में लेबर इम्प्लॉइड है, फू
सेसिंग में लेबर इम्प्लॉइड है, लेदर, फुटवियर, वुडेन, फर्नीचर जगत में बहुत से लेबर्स इम्प्लॉइड हैं । आप इन सेक्टर्स के लि
ई अच्छी स्कीम निकालिए । पीएलआई से सब कुछ नहीं होने वाला है । पीएलआई एक सब्सिडी है । एक सब्सिडी से
क्टर नहीं बनने वाला है । हम सेमी कंडक्टर्स में पीएलआई दे रहे हैं, आपको पता है कि चीन ने सेमी कंडक्टर्स में 140 बिलि
लर का इन्वेस्टमेंट किया है । ताइवान में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, आज यूएस में जाकर 100 बिलियन डॉलर्स का से
डक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं । अगर हम सिर्फ सेमी कंडक्टर्स में ही रखें, तो हम कंपीट नहीं कर पाएंगे और रोजगार नहीं
ूगे ।

महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो वास्तविक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेड्रिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें उन पर भी ध्यान दे
हिए । पीएलआई जैसी और भी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स आनी चाहिए ।

ON. CHAIRPERSON: Just to remind you that you have already spoken for half-an-hour.

RI GAURAV GOGOI: Thank you, Sir.

महोदय, उत्तर पूर्वांचल की बात आती है । उत्तर पूर्वांचल में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में इंडस्ट्रियल
त कम है । मैं चाहता हूं कि यूपीए के समय में जो स्कीम थी, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी थी, उस
बारा लागू करिए । जब आपको कोई स्कीम काटनी होती है, तो आप बोलते हैं कि इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं दे
हिए, इंडस्ट्री को कैपिटल सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो फिर पीएलआई में कैसे देते हैं? अगर पीएलआई में दे सकते हैं, तो आ
ं नहीं एक कंडीशन लगाते हैं कि पीएलआई में इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री नागालैंड में लगेगी । पीएलआई की टेक्सटाइल
स्ट्री मेघालय में लगेगी । पीएलआई की फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री त्रिपुरा में लगेगी । आप इस प्रकार की नीति क्यों नहीं बन

महोदय, आज केरल राज्य में बहुत से लोग रबड़ प्लांटेशन में काम करते हैं । चाय बागान के प्लांटेशन में लगभग 10 ल
ा काम करते हैं । हमको इन लोगों को भी देखना है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है । इनकी
ी मांग है कि ये जो दो प्लांटेशन्स हैं, specifically tea and rubber should be taken out from the Ministry of Comme
d put in the Ministry of Agriculture so that the small farmers can get access to subsidies, training and high qua
nting material. The Tocklai Tea Research Centre in Assam is craving for funds, and I hope that you will give th
t.

Sir, I want to slowly come down to my conclusion. मैं सिर्फ नकारात्मक बात नहीं बोलना चाहता हूं । मैं थ कारात्मक बात भी बोलना चाहता हूं ।?(व्यवधान)

ON. CHAIRPERSON: Hon. Member, not slowly, but speed it up.

RI GAURAV GOGOI: Sir, I will try it. मोबाइल में जो देखते हैं, वह जिस स्पीड में आता है, मैं उस तरह से नहीं ऊंगा ।?(व्यवधान)

ON. CHAIRPERSON: No, I am not telling you to go 5G.

RI GAURAV GOGOI : Sir, I would request this Government that instead of investing on big Corporatio est in human capital and invest in higher education.

The Peking University in China, वह आज यूएस की न्यूज में 39 रैंक पर है और हमारी जो टॉप पर्फार्मिंग यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बेंगलुरु) है, वह 551 रैंकिंग पर है । So, we have to invest in higher education, and ve to invest in science. This is what our India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said that for India ogress we must cultivate a scientific temper. We do not see that scientific temper. This is a Government t ieves in myths and mythologies, in creating fake narratives, in creating fake victims, but does not believe ence.

So, I would urge you to look at start-ups. I want to point to a very alarming situation. स्टार्ट अप्स की बात क यूनिकॉर्न की बात करते हैं । आपको पता है कि आज स्टार्ट अप सेक्टर में टेक वैल्यूएशंस गिर रही है । आपको पता है कि अ र्ट अप सेक्टर में फंडिग कम हो रही है । मार्च, 2022 में स्टार्ट अप में 3.5 बिलियन का निवेश हुआ था, दिसंबर तक मंथ वेस्टमेंट 3.5 बिलियन से 900 मिलियन हो गया । आज यूएस में 330 बिलियन की स्टार्ट अप इंडस्ट्री है । आज ह केटिबिलिटी को लेकर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दीजिए ।

महोदय, आप सर्विसेज़ पर ध्यान देखिए । हम देख रहे हैं कि अगर आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई पकड़ रहा हमारा मध्यम वर्ग पकड़ रहा है । Private consumption is happening and that is keeping the economy alive. A ere is this investment going? It is going in trade, hotels, restaurants, transport, storage, communication, social a rsonal services. The services sector contributes 53 per cent to our gross value addition. So, this is where we ha nvest, that is in our services. We have to invest in cities and towns.

Look at what is happening in Joshimath. आज हिमालयन रेंज से हमारे ऐसे बहुत से शहर हैं, जहां पर लोड बे पेसिटी से ज्यादा डेवलेपमेंट, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म का फुटफॉल हो रहा है ।

सर, हमें नियंत्रण बनाना है । हमें टूरिज्म भी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए । आज हम देख रहे हैं टेनेबिलिटी के तहत आपकी सरकार ने वायु प्रदूषण पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम निकाला और आज वह प्रोग्राम पूरी तरह फल हो गया है । वह पूरी तरह से विफल हो गया है । सारे शहर, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में सिटी एयर एक्शन प्ल कालते हैं, वे सारे कार्बन कॉपी हैं, कट एंड कॉपी-पेस्ट हैं । कुछ भी नहीं हो रहा है । सारा पैसा, जो कि 15वें फाइनेंस कमीश दिया गया था, वह व्यर्थ हो गया है । आप मिलेट की बात करते हैं, श्री अन्न की बात करते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ पने मिलेट पर इतना जोर दिया, लेकिन मिलेट के साथ-साथ मेरा सुझाव यह होगा कि इसको डिसेन्ट्रलाइज प्रोक्योरमेंट औ सेन्ट्रलाइज डिस्ट्रिब्यूशन से जोड़ा जाए, आईसीडीएस और पीडीएस से जोड़ा जाए, क्योंकि मालन्यूट्रिशन आज भी एक ब ी समस्या है । अगर आज मालन्यूट्रिशन को हमें खत्म करना है तो पीडीएस के द्वारा मिलेट और आईसीडीएस के द्व गनवाड़ी सेन्टर्स में लोगों को यह जानकारी जानी चाहिए ।

अंत में मैं इस सरकार को यह बोलना चाहूंगा कि इस सरकार को पारदर्शी होना चाहिए । लोकतंत्र का मूल्य है पारद
ा, लेकिन जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं, विपक्ष उठाता है या मीडिया उठाती है, चूँकि हम भी लोकतंत्र के पार्ट हैं इसि
क्ष भी जनहित में दबाव बनाता है, लेकिन हम जब भी सवाल उठाते हैं तो हमारे सवालों को नजरअंदाज किया जाता है । हम
वाज को बंद किया जाता है । जब हम पूछते हैं कि पीएम केयर्स फंड, जो कि एक सरकारी फंड नहीं है, उस पर सरकार
ो कैसे लगा? हुआवेई जैसी चाइनीज़ कंपनी ने सात करोड़ रुपये कैसे दिए? जब यह पूछा जाता है तो कोई आवाज नहीं आत
रटीआई तक का जवाब नहीं आता । जब हम मांग करते हैं कि ऐसे वक्त में, जब एक पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट वैल्यूए
उन हो रहा था, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और सर्कूलर ट्रेडिंग को लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे, जब कोई रिटेल इन्वेस्टर
पनी के एफपीओ में नहीं आया तो किसने दबाव बनाया कि एसबीआई और एलआईसी ऐसे संवेदनशील समय पर एंकर इंवे
? एसबीआई और एलआईसी पर किसने दबाव बनाया? हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और पब्लिक फेथ और पब्लिक मनी
भाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है तो मैं सरकार से बोलूंगा कि वह साहस दिखाए और अगर जांच हो तो जांच से न डे
एम केयर्स फंड पर भी जांच हो और अडानी तथा एलआईसी, एसबीआई का जो पूरा मुद्दा है, उस पर जेपीसी गठित करने
ारी मांग है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, धन्यवाद । प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्म
ारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अमृत काल में और हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यह बजट पेश हुआ
कि चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे आदिवासी हों, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, चाहे युवा हों, च
हिलाएं हों, चाहे आम जन हों, सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है । इसके साथ-साथ मैं कह सकता हूँ कि सभी वर्गों ने, उसमें च
डिल क्लास हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हम ग्लोबली बात करें या मीडिया की बात करें तो किसी ने भी यह बात नहीं कही कि
क्शन बजट है । चूँकि चुनाव वर्ष 2024 में होने हैं । यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बजट है और एक लंबी सोच का बजट है ।
क विजनरी बजट है । यह देश हित का बजट है और सभी के हित वाला बजट है । यही कारण है कि जिस हिसाब से प्रधान म
दी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है, उसकी वजह से आज भारत पांचवें पायदान पर है । आज वर्ल्ड में भा
वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि वर्ष 2014 में 10वें स्थान पर थी । यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है । इ
म जन में एक तरह का आत्मविश्वास डेवलप हुआ है कि हम अगले 100 सालों में कैसा भारत बनाने वाले हैं ।

00hrs

मुझे यह जानकार आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के हमारे साथी और राहुल जी किस हिसाब से कहते हैं कि हमारी जीडीपी
तिशत बढ़ेगी । उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन इकोनोमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर
दिया है । मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी की बात करूंगा, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड कह रह
उसकी रिपोर्ट में कहा गया है : "India better positioned to navigate global headwinds than other major emerg
nomies". The Economic Survey has predicted the growth at the rate of 7 per cent in 2023.

ON. CHAIRPERSON: If the House agrees, we may extend the House for two hours till 8 o'clock.

दीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, सदन का समय दो घण्टे के
ा दिया जाए ।

ON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended for two hours though speech will not extend for t
urs.

पी. पी. चौधरी: Yes, Sir, I am assuming that. सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड की प्रेडिक्शन के हिसाब से इंडिया वर्ष 20
फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनोमी है । मैं यह कह सकता हूं कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, जबकि पूरे विश्व में एक डार्क होराइ

ा हुआ है । अगर हम सारी इकोनोमीज को कम्पेयर करके देखें तो आज हमारी इकोनोमी पैंडेमिक कोविड होने के बाद
स हिसाब से हमारी इकोनोमी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभाला गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है ।

01 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair)*

इकोनोमिस्ट्स की जो प्रेडिक्शन्स हैं, मैं यह कह सकता हूं कि 7 प्रतिशत ग्रोथ की प्रेडिक्शन है और उसके साथ-स
फ्लेशन सिर्फ 6.9 प्रतिशत है । हमारी ग्रोथ हाई ग्रोथ है और हमारी मॉडरेट इन्फ्लेशन है । अगर हम दूसरी इकोनोमीज की
, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनोमी यूएसए की बात करें, उसकी ग्रोथ सिर्फ 1.7 प्रतिशत है और भारत की ग्रोथ 7 प्रतिशत
प इसका डिफ्रेंस सोच सकते हैं । अगर हम दोनों को कम्पेयर करें तो इंडिया की इकोनामी 7 प्रतिशत की ग्रोथ पर चल रह
र अमेरिका की 1.7 प्रतिशत ग्रोथ कर रही है । जहां तक वहां के इन्फ्लेशन का सवाल है, वह 8.1 प्रतिशत है । इसलिए हम
कते हैं कि इंडिया में हाई ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन है और अमेरिका में लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन है । यदि हम जर्मनी
न करें, तो वहां 1.6 प्रतिशत ग्रोथ है और इन्फ्लेशन 8.4 प्रतिशत है । इस तरह वहां पर भी लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन है
री डेवलप्ड इकोनोमीज की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वे भी इंडिया से बेटर पोजीशन में नहीं हैं । आज पूरे विश्व में अ
देखें तो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है । मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा
dia to surpass Japan and Germany to become the third-largest economy by 2027".

यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे बजट में जो आधारभूत ढांचा रखा गया
नींव रखी गयी है, वह बहुत सॉलिड है और उनका विज़न है कि वर्ष 2027 तक हम जापान और जर्मनी को भी सरपास कर स
फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा है : "India's plan to take on China as South Asia's favourite lender. With the priv
tor's help, New Delhi has stepped up spending on infrastructure in neighbouring countries also".

कहने का मतलब है कि आज जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनोमी डिस्ट्रॉय कर दी गई है, वे बिना फैक
जांच किए कह रहे हैं । वैसे पूरा देश इनको गंभीरता से लेता भी नहीं है । अगर उनको यही पता नहीं है कि सात प्रतिशत
च प्रतिशत में कितना फर्क है । कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि पांच प्रतिशत ग्रो करेगी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड
डिक्शन है कि 7 प्रतिशत ग्रो करेगी । इनको यह जान लेना चाहिए । इस बारे में, मैं कहना चाहूंगा :

?कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दे दी पतवार हमें,
लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको,
कि इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें ।?

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात है, जब संसद में बड़ा शोरगुल हु
कहा गया था कि बहुत महंगाई है, यह है, वह है, लेकिन इन्होंने यह कम्पेयर नहीं किया कि जो ग्लोबल इफेक्ट है, वह इण्डि
नहीं और इकोनॉमीज पर हुआ । अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी जाए तो मैं दो-तीन कंट्रीज की कम्पेयर करूंगा । यूनाइ
ट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी इन सभी से इण्डिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है । अगर इण्डिया में कॉस्ट अ
विंग 416 डॉलर है तो अमेरिका में 2112 डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम में 1804 डॉलर है और जर्मनी में 1325 डॉलर है । अ
स्ट ऑफ लिविंग इण्डिया में सबसे कम है ।

सर, ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग की बात करें, मैं मेन कंटेंट पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं यह बता देता हूं कि जिस हिस
पहले इनकम टैक्स रिटर्न में कॉम्पलैक्सिटीज थीं, जिस हिसाब से एक टैक्स पेयर को प्रॉब्लम होती थी तो इसमें एक फेसल
सेसमेंट सिस्टम को प्रमोट किया गया । इससे एफिशिएंसी बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी । इन्क्री
फिशिएंसी से आईटीआर फाइलिंग ज्यादा हुई और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एनहांस अकाउंटेबिलिटी बढ़ने की वजह
प्शन के केसेज़ रिड्यूस हुए । जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए हरासमेंट के मामले थे, वे कम हुए और कॉस्ट इफेक्टिव टा
ा और टाइम में भी कमी आई ।

महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विज़न है, वह बहुत अच्छी त
फुलफिल हो रहा है । जिस हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न में रिफण्ड के मामले थे, पहले उनमें महीनों लग जाते थे, सालों
ते थे । बिज़नेसमैन परेशान होते थे । आप सोचिए कि कौन इस तरह के भारत में बिजनेस करेगा और बिजनेस बाहर जाते
ोंकि उनके रिफण्ड वगैरह टाइम पर नहीं मिलते थे । अब ज्यों ही आपने आईटीआर फाइल किया, त्यों ही कुछ दिनों के अं
फण्ड हो जाता है । Tax Department has issued Rs.2.4 trillion tax refunds between 1st April, 2022 and 10th Janu
23. आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टैक्स रिफण्ड मिला है । मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम प्रिवियस ईयर में इंप्रूव
वें तो 58.47 परसेंट का पहले साल से ज्यादा इंप्रूवमेंट है । जहां जीएसटी रिजीम की बात करें तो एनहांस ट्रांसपेरेंसी
सेशन सिस्टम लागू किया । उससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर की डिग्निटी एन्श्योर हुई । हम जन-धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी
न करते हैं । स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात बार-बार होती है, क्योंकि वह बड़े परेशान थे, उनकी कांग्रेस पार्टी परेशान थी
ार हम एक रुपया भेजते हैं, जो लाभार्थी है, जो गरीब है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है, उन्होंने खुद ने माना कि उस
पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में लीकेज हो जाते हैं । फर्जी बेनिफिशियरी कौन होते थे? उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया, क
र्ट नहीं किया कि इसको खत्म किया जाए ।

मैं धन्यवाद देता हूं, पूरा देश धन्यवाद देता है, पूरे देश के गरीब धन्यवाद देते हैं, पूरे देश के लाभार्थी मोदी जी को धन्य
हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से जन धन अकाउण्ट खुलवाए तो उस समय मजाक बनाया जा रहा था । आज देश में जो जन
काउण्ट हैं और जिस हिसाब से जन धन अकाउण्ट और आधार हैं, इस स्कीम के तहत आज टोटल जन धन अकाउण्ट देश
करोड़ से भी ज्यादा हैं । देश में जो आधार होल्डर हैं, वे करीब 136 करोड़ के आस-पास हैं । यह अपने आप में बहुत बड़ी
आप देख लीजिए कि आज देश के हर व्यक्ति के पास आधार है । उसको चिंता नहीं है । उसको यह पता है कि अगर मोदी
ी दिल्ली से एक लाभार्थी के रूप में पैसे भेजेंगे तो सीधे मेरे खाते में जाएंगे, कोई लीकेज नहीं होगा । उसके अलावा अ
बाइल फोन हैं, जिन पर मैसेज वगैरह मिलता है । हमारे देश में करीब 1.2 बिलियन, मतलब करीब 600 मिलियन स्मार्ट फ
र्स हैं ।

आज हम कह सकते हैं कि trinity की वजह से डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, जो fake beneficiaries थे, बहुत ब
केज रुका और सीधा उनके पास पहुंचा । हम पहले पूछते थे कि आपके पास सरकार का पैसा आता है । वे कहते थे कि अ
क हजार रुपए आना है, तो वे पांच सौ रुपए बीच में खा जाते थे और कई फर्जी बेनिफिशरीज बन जाते थे । लेकिन आज
स्या हमारे यहां नहीं है । इसका धन्यवाद प्रधान मंत्री मोदी जी को जाता है । देश का गरीब, जो समाज के अंतिम छोर
क्ति बैठा है, वह खुश है कि उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचता है और स्टेबल और ट्रांसपैरेंट रिजीम की वजह से करीब 27 ल
ोड़ रुपए बेनिफिशरीज को पहुंचे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 27 लाख करोड़ रुपए सिर्फ डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम
चे हैं । अगर यह लिकेज होता, तो आप अनुमान लगाइए, मोटे-मोटे तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लिकेज होता
र्जी लोगों के पास जाता या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता । उन बेनिफिशरीज, उन गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंचता । आज
ख करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे पहुंचे ।

जब यह आधार आया, तो कांग्रेस के नेता बार-बार कहने लगे कि यह आधार बीजेपी का surveillance tool है । यह गरी
साथ मजाक है । क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीबों के खातों में सीधा पैसा पहुंचे । जब उन्
ड़ा कि आधार सिर्फ surveillance के लिए है, तो आप चाहते हैं कि आधार गरीबों को जारी न हो । लेकिन इसकी वजह से ब
ा लाभ हुआ है ।

प्रधान मंत्री मोदी जी के विजन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्र
है, enhance हुई । Employment का enhancement हुआ है । Consequential effect की वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़
र जिस हिसाब से self-reliant India, अमृतकाल में, there is enhanced production of semiconductor chips. यह अप
प में बहुत बड़ी बात है । Semiconductor chips इंडिया में बनना और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होना, एयरक्राफ्ट इंक्रीज हो
र इनका एक्सपोर्ट होना, यह अपने-आप में बड़ी बात है ।

एक समय था, जब हम लोग कहते थे कि लगभग चार लाख करोड़ रुपए के electronic devices, medical devices सी अन्य तरह के डिवाइसेज हों, वे हमें इम्पोर्ट करने चाहिए । उनके इम्पोर्ट से हमारी फॉरेन करेंसी विदेशों में जाती थी, लेकि ज मोदी जी का विजन, प्रधान मंत्री जी का विजन है कि ये चीजें इंडिया में बननी चाहिए । Electronic devices, medi vices या मोबाइल से संबंधित हों, इनके यहां मैन्युफैक्चर होने से यहां पर रोजगार मिलेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी और गे बढ़ेगा । आज हम यह देख सकते हैं ।

अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूं, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है । There is improved infrastructure for nsport, increased private participation and improved connectivity. आज यह देखने को मिलता है । अगर हम मोबा न इम्पोर्ट की बात करें तो पहले हम यह इम्पोर्ट करते थे । आज हमारे यहां मोबाइल फोन्स इम्पोर्ट काफी डिक्रीज हो गय र मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट इनक्रीज हुआ है । आज हम मोबाइल फोन्स के मेजर एक्सपोर्टर हैं । वर्ष 2022 में हम सपोर्ट करीब 5.8 बिलियन डॉलर का हुआ है । यह अपने-आप में एक रिकॉर्ड है । हम एस्टिमेटेड कह रहे हैं कि वर्ष 2023 स हिसाब से स्पीड बढ़ेगी, उसके हिसाब से 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा ।

अगर हम खिलौने की बात करें तो चाइना से खिलौने तक आते थे, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शिता है कि हम ये चीजें य युफैक्चर नहीं करेंगे, तो हमें कितना लॉस होगा, हमारी कितनी फॉरेन करेंसी बेकार जाएगी । आज करीब टॉयज का इम्पोर्ट शत डिक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट 70 प्रतिशत इंक्रीज हुआ है । आज उसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा फायदा हुआ है । उस धा फायदा हमारे एसएमइज को गया । आज हमारे देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज में एमएसएमइज हैं । एमएसएमई में गांव टे-छोटे लोग इनवॉल्व्ड हैं ।

मोदी जी का यह विज़न है कि हमारे एमएसएमईज़ कैसे और आगे बढ़ें, उनका प्रोडक्शन और ज्यादा कैसे बढ़े, लोगों से रोजगार मिले ।

जहाँ डिफेंस एक्सपोर्ट की बात है, तो यह इंडस्ट्री अपने आप में बहुत मजबूत हुई है । लगभग सिक्स टाइम्स एक्सपोर्ट बढ़ ने आप में एक बहुत बड़ी बात है । हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 14 हजार करोड़ रुपए वर्ष 2022 में क्रॉस कर चुका है ने enhanced private participation and increased FDI की वजह से, जो भी हमारा आगे का फ्यूचर है, इसमें बहुत ज़बरद

हम indigenous aircraft carrier INS Vikrant की बात कर रहे थे । कम से कम उनको यह चीज देखनी थी कि देश में छे काम हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा करें । लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का एक ही काम है, जबकि पूरा देश प्रशंसा करता है, खुश है । लेकिन इनको तकलीफ है । आप इनको कंस्ट्रक्टिव बात बताएं, लेकिन आप 24 ऑवर डेस्ट्रक्टिव एटिट्यूड रखते र हर बात के लिए डेस्ट्रक्टिव एटिट्यूड रखते हैं । जो फिगर है, ये उनको भी स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते हैं । टिट्यूड देशहित में नहीं है । यह इनको छोड़ना पड़ेगा । यदि ये उसे नहीं छोड़ेंगे, तो जनता इनसे छुड़वा देगी ।

जहाँ तक खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की बात है, क्या कभी हम सोच सकते थे कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का इत ना काम गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से, लगभग एक लाख करोड़ रुपए टर्नओवर हुआ है और खादी की सेल फोर टाइ ीज हुई है । इसका direct consequential effect क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का सीधा अ रल इकोनॉमी पर है । अर्बन इलाके में रूरल माइग्रेन कम होगा क्योंकि जब रूरल में जॉब्स नहीं होते हैं, तो अर्बन में माइग्रेश ना है । हमारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो अ टर्स हैं, उन पर बर्डेन कम ही होगा । खास करके गांव में जो खेती है, खेती के साथ-साथ जब ऑफसीज़न होता है, उसमें कु म नहीं होता है । ये जो छोटे-छोटे एमएसएमईज़ हैं, महिलाएं हैं, जो वीवर्स हैं और इंडिजिनस क्राफ्ट्समेन हैं, उनको प्रोत्सा लेगा ।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से स्मॉल बिज़नेसेज़ हैं, उनका वास्ता कभी बैंक्स से नहीं था । फॉर्मल बैंकिंग से उन केज हुआ । पहली बार इतना बड़ा काम हुआ । सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कभी भी कोलैटेरल लोन नहीं मिलता थ किन मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विज़न की वजह से, आज उनको केवल कोलैटेरल लोन ही नहीं, बल्कि पीएम स्वनि

जना के तहत उनको एफोर्डेबल लोन भी मिल रहा है । इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी एन्हांस हुआ है और increas
ilability of credit उनको मिला है । यदि हम फिगर्स पर जाएं, तो कुल 95 per cent of the total request for loan has be
ctioned.

ये लोग बिना फिगर्स के बात करते हैं और कहते हैं कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ । लेकिन ये गवर्नमेंट के फिगर
95 परसेंट लोन रिक्वेस्ट्स सैंक्शन हुए । इससे कौन एम्पॉवर्ड हुए? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, जो कभी बैंक्स के पास न
च पाते हैं, आज उनको एक शक्ति मिली है, एक ताकत मिली है और यह हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है । इ
ग्लॉयमेंट भी जेनरेट होता है ।

आज हम देखते हैं कि चाहे एक छोटा कुम्हार हो, वह घड़े या मटकियाँ बेचता हो या मिट्टी के बर्तन बेचता हो, चाहे स
ले हों, उनके ठेले पर कुछ भी हों, वे डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमेशा प्राथमिकता देते हैं । हम लोग जितना डिजिटल ट्रांजैक
हीं कर पाते हैं, वे लोग उतना ही ज्यादा करते हैं । वे लोग पास में पैसे रखना नहीं चाहते हैं । वे पैसे सीधे अपने बैंक के खाते
जते हैं । इस तरह से स्मॉल बिज़नेसमेन का फार्मल बैंक्स से लिंकेज होना इकोनॉमी को और भी ग्रोथ देता है ।

जिस हिसाब से, प्रधानमंत्री जी का विज़न है- ?focus on innovation and entrepreneurship?, यह जो Global Innovat
dex है, इसमें पहले इंडिया की रैंकिंग 81 थी, अब वह 40 पर आ गई है ।

वर्ष 2022 में यह रैंकिंग 40 पर आई है । इतनी बड़ी इनक्रीज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है । इस इनक्रीज्ड इनोवेशन
सारी इकोनॉमिक ग्रोथ इनक्रीज होगी और हमारी quality of product and services भी इनक्रीज होगी । यदि हम नंबर अ
र्टअप्स की बात करें, तो वर्ष 2022 में 90,000 स्टार्टअप्स हैं और हमारे 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं । हम यदि इन सारी बातों
वें और ओवरऑल देखें, चाहे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात देखें, चाहे हमारे सभी वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने य
र्लियामेंट में जो बातें कही हैं, उनको देखें और जिस हिसाब से ग्लोबली प्रधान मंत्री जी का जो इम्पैक्ट है, उस हिसाब से मैं क
हता हूं, the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, is the most popular leader in the world.

इसका प्रमाण है कि जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे हुआ है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी की सर्वे में
सेंटेज है, वह 78 परसेंट है । अमेरिका के प्रेसिडेंट की रेटिंग 40 परसेंट है । आप सोचकर देखिए कि उनके नीचे दूसरे नंबर
क्सिको के प्रेसिडेंट की रेटिंग 68 परसेंट है, स्विटजर्लेंड के प्रेसिडेंट 62 परसेंट, ऑस्ट्रेलिया के पीएम 58 परसेंट, ब्राजील
सिडेंट 50 परसेंट और कनाडा और यूएस के प्रेसिडेंट 40 परसेंट पर हैं, दूसरी लिस्ट तो बहुत लंबी है ।

आज एक मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दि वर्ल्ड होने का मतलब देश की इकोनॉमी को लेकर पूरे विश्व के साथ आपके रिलेश
। वे इसी कारण हैं कि इंडिया को मोदी जी ने विश्व की पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है । यह सबसे बड़ा कारण है कि अ
दी जी का जो रोल है, वह अपने आप में बहुत बड़ा है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब मैं बजट की बात करता हूं, अगर मैं नटशेल में समाप्त करना चाहूंगा कि इस बजट से
पज, ऑब्जेक्ट और इंटेंट साफ जाहिर होता है, वह है, to maintain and continue growth. जो पहले की ग्रोथ है, उसे मे
र कन्टिन्यू करना है । जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह इनवेस्टमेंट का है । इनवेस्टमेंट बेसिकली एक फाउंडेशन है और
लिए बहुत ही स्ट्राँग फाउंडेशन है, जो कि लॉन्ग टर्म है । यह बजट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है । आज तक हम देखते हैं कि ब
क्शन ओरिएंटेड होते हैं । जब चुनाव आते हैं, तो चुनावी बजट हो जाता है, लेकिन उनको देश की चिंता नहीं होती । यह ब
की चिंता है । देश पहले है, पार्टी बाद में है । अत: आज देश को मजबूत करने के लिए और देश के इनफ्रास्ट्रक्चर को मज
ने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं । लेकिन हमारा इनवेस्टमेंट लॉन्ग-टर्म है ।

अगर हम इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट देखें कि इनवेस्टमेंट के कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स क्या होंगे, तो मैं बताना चाहू
। इससे हमारा इनफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा । इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगी, जीडीपी बेटर होगी । Ease of living and ease
ng business बेटर होगा and we can create more jobs through MSEs.

सर, इस बजट से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि एमएसएमईज वगैरह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इसके साथ-स
फेयर स्कीम्ज का भी ध्यान रखा गया है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसे इससे मदद मिलेगी । अब
स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आता हूं । यह सब करते हुए prudent financial management का ध्यान रखना है । यह अपने आप
क बहुत बड़ी बात है कि बजट में prudent financial management को भी बैलेंस किया गया है, जिससे हमारा डेफिसिट रिड
ा है और हमारा रेवेन्यू इनक्रीज हुआ है ।

यदि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो वर्ष 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 7 लाख 28 हजार करोड़ रुपए थ
2023-24 में, बजट में जो प्रावधान रखा है, वह करीब 10 लाख करोड़ रुपए का रखा है, जो कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर
ए पहले के साल से करीब 37 परसेंट ही इनक्रीज है । इस बात को ध्यान में रखा गया है, देश के फ्यूचर के लिए ध्यान में र
ा है । हम देखें कि उसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टिट्यूशंस हैं, उनसे 4 लाख करोड़ मिलेगा ।

सभापति जी, अगर टोटल देखें तो 14 लाख करोड़ रुपये हो जाता है । गोगोई जी बात कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि
40 परसेंट लेबर कम्पोनेंट बढ़ेगा । चाहे रूरल एम्प्लॉयमेंट हो या अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो, हम यदि 10 लाख करोड़ रुपये केपि
सपेंडिचर का देखें, उसमें लगभग 4 हजार करोड़ रुपये लेबर कम्पोनेंट बन जाता है । देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस प्रव
बजट रखा गया है, उससे रोजगार बढ़ेगा । इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार का अपना स्वयं का इनवेस्टमेंट है । रेलवे, रोड, च
ान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, रिन्युएबल एनर्जी, जल जीवन मिशन हो और राज्य सरकारों के
1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल तक के लिए रखा है । यह राज्य सरकार की च्वाइस है
किस मद में कहां खर्चा करे । यदि हम केपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट्स देखें, तो देखेंगे कि एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होत
दि केपिटल एक्सपेंडिचर न हो तो मल्टीप्लाई इफेक्ट नहीं होगा । मैं उदाहरण देता हूं कि यदि सौ रुपये केपिटल एक्सपेंडि
लिए रखे हैं तो सेम ईयर में सौ रुपये की वैल्यू 245 इकोनॉमी में एड होती है । यह विजन प्रधान मंत्री मोदी जी का है कि
ास्ट्रक्चर के अंदर केपिटल एक्सपेंडिचर में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उस पर ध्
या गया है । मैंने पहले साल का उदाहरण 245 रुपये का दिया है । यही 10 लाख करोड़ रुपये का आने वाले वर्षों में मल्टीप्
क्ट 450 रुपये इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा । यही कारण है कि केपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में ज्यादा प्रावधान रख

महोदय, इससे प्राइवेट सेक्टर को भी इनक्रेजमेंट मिलेगा क्योंकि उन्हें पता है कि जब सरकार का केपिटल एक्सपेंडिच
प्राइवेट सेक्टर भी उसमें सम्मिलित होंगे । जहां तक मैं वेलफेयर स्कीम की बात करूं, इसमें जल जीवन मिशन की बात क
हमारा 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला देश है । जल देना राज्य सरकार का काम होता है लेकिन जल जीवन मि
करीब 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है और यह बुनियादी जरूरत है । यदि आप देखें तो इ
गार सृजन भी होगा । राजस्थान के बारे में कहूंगा कि वह पानी के लिए तरस रहा है । पानी की कमी खास कर पश्चि
स्थान में है । प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन में वहां की कांग्रेस सरकार को 27 हजार करोड़ रुपये दिए हैं लेकिन कां
कार की हालत यह है कि उसमें से सिर्फ 2700 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए हैं । राजस्थान की गरीब जनता जो ढाणियों
ती है, उन्हें पानी पहुंचाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन वह काम नहीं हो पा रहा है ।

सभापति जी, जहां तक प्रधान मंत्री आवास योजना का मामला है, उसमें वेलफेयर स्कीम के तहत करीब 79590 कर
ये का प्रावधान रखा गया है, जो कि 66 परसेंट की वृद्धि है । मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करना चाहूंगा ।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । प्रधान मंत्री जी का विजन देखिए । जो गरीब हैं, गांवों
नके घर नहीं हैं, जो रोड पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं और खेतों में खुले में रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रधान मंत्री आव
जना के तहत 66 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि उन्हें घर मिल सके । रूरल में करीब 54,487 करोड़ रुपये का प्रावध
या गया है, जो कि 172 प्रतिशत ज्यादा है । इससे गांवों में जब मकान बनेंगे, तो रोजगार पैदा होंगे, यानी डायरेक्ट इम्प्लॉय
र इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट ।

ON. CHAIRPERSON: Please conclude.

RI P. P. CHAUDHARY : Sir, I am speaking within the time allotted to my Party.

ON. CHAIRPERSON: You have already taken 32 minutes. Please conclude now.

पी. पी. चौधरी: सर, प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारी फिस्कल डेफिसिट 5.9 प्रतिशत है । पहले यह 6.4 प्रति । रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का केवल 2.9 प्रतिशत है । इससे एमएसएमई जॉब्स में भारत सरकार की लोन स्कीम गारंटी उट टर्न लगभग 34 प्रतिशत इनक्रीज हुआ है । एमएसएमई में टैक्स बेनिफिट दिया गया है तथा टैक्स इन्सेंटिव को-ऑपरेटि भी दिया है । को-ऑपरेटिव्स को इन्करेज करने के लिए उनके टैक्स को 22 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया है । क इनकम टैक्स की बात है, वह 7 लाख रुपये तक कुछ नहीं है । इसको सिम्प्लीफाई किया है । उसका पर्पज़ यह है कि अधि जम्प्शन हो, डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन हो और अधिक रोजगार जेनरेट हो, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े ।

महोदय, अब फार्मर्स की बात करते हैं । मैं खुद किसान हूं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने बैलों से खेती की है । न का सारा काम किया है । मैं किसानों की तकलीफ जानता हूं । मोदी जी के विजन में हमने पहली बार देखा कि स्टो सिलिटी हुई है, जिसमें किसान को सबसे ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी । स्टोरेज नहीं ह वजह से वह बाजार में उसी समय अपना अनाज बेच देता था । इसमें हम भी शामिल थे । हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं हो लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी को इन्करेज किया गया है, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर हो, चाहे को-ऑपरेटिव के लेवल पर हो ।

सर, मैं उनके विजन की दाद देता हूं । हमारे राजस्थान में जो बाजरा होता है, उसका खरीदार नहीं मिलता है । उसे ुओं को फॉडर के रूप में देते हैं, लेकिन मिलेट को इंटरनेशनल लेवेल तक पहुंचाना तथा इन्करेज करना प्रधान मंत्री मोदी अपने-आप में एक बड़ा विजन है, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है ।

ON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

RI P. P. CHAUDHARY: I am concluding, Sir.

जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें आज तकनीक जितनी ज्यादा किसानों के लिए यूज होगी, उसकी कॉस्ट अ डक्शन उतनी कम होगी । उसके साथ-साथ किसानों को प्रमोट करने के लिए, उसकी एलाइड एक्टिविटीज हेतु खेती ही न के साथ-साथ किसानों को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी अगर साथ में करें, तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, इस धान प्रधान मंत्री जी ने प्रस्तुत बजट में रखा है । पीएम किसान निधि के लिए सभी किसान पात्र हैं । आज हम किसानों के ब ते हैं तो सुनते हैं कि मोदी जी की वजह से कम से कम 6 हजार रुपये उन्हें मिलते हैं, जिससे वे खाद ले सकते हैं । जहां त सल बीमा की बात करें, तो यह काम राज्य सरकार का है कि वह एंट्री सही करे । एंट्री सही न करने से खासतौर पर राजस्थ किसानों को दिक्कतें होती हैं । हम बार-बार कांग्रेस सरकार से कहते हैं कि आप एंट्री सही करें, ताकि किसानों को फसल बी जना का फायदा मिल सके, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है । जहां तक एफपीओ की बात है, वह भी आने वाले समय फी यूजफुल होगा ।

सर, आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रधान मंत्री जी का मिशन है, ताकि उनके घर बनें, रोजगार मिले, उनकी नेट बूत हो और साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में करीब 38 हजार 800 शिक्षक और स्टाफ को नियुक्त क ने-आप में बहुत बड़ी बात है ।

महोदय, मैं महिलाओं की सेविंग्स के लिए बताना चाहूँगा । एम्पावरमेंट ऑफ दी वुमेन । सर, महिलाओं की बात सुनिए, न महिलाएं नाराज होंगी, अगर आप नहीं सुनोगे तो महिलाएं नाराज होंगी । आप देखिए महिला सम्मान बचत पत्र में 7.5 पर रेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा और स्वयं सहायता समूह के बारे में बजट में प्रावधान किया गया है । जहाँ मेरा लोक सभा वहाँ पर आदिवासी महिलाएं रोड पर बैठकर सीताफल को एक रुपये में बेचती थीं । आज स्वयं सहायता समूह को यह देख उनके जो लाखों स्वयं सहायता समूह हैं, उन पर ध्यान देना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना का बहुत बड़ा पार्ट है ।

महोदय, अभी गोगोई जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की । आप देखिए कि जो दूर-दराज
वे हैं, आज जब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए । नेशनल डिजि
इब्रेरी, जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे कोई कहीं हो तो उसमें एक कॉस्ट इफेक्टिव,
सेसिबिलिटी बनेगी, क्वालिटी सर्विस मिलेगी और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए उसमें लाइब्रेरी तक हमारे बच्चों
सेसिबिलिटी बनेगी । 150 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी हैं । 150 न्यू नर्सिंग कॉलेजेज का
वधान रखा गया है, वह अपने आपमें बहुत बड़ी बात है । जहाँ तक सामान्य एलोकेशन की बात है, मैं राजस्थान की बात क
राजस्थान को बजट में पहले करीब 20,360 करोड़ रुपये मिले थे । अबकी बार 61,552 करोड़ रुपये राजस्थान को बजट
ले हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, दोनों का मिलाकर जो पहले औसत
स्थान के लिए, रेलवे के लिए वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक 682 करोड़ रुपये था, वह अब इस बजट में 9,532 करोड़ रुपये
या गया है । अगर राजस्थान के डेब्ट की बात करें, अगर फिस्कल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो मैं
कता हूँ कि सारे देश के जो स्टेट हैं, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 29 परसेंट ऑफ दी जीएसडीपी है, लेकिन राजस्थान का
एसडीपी है, वह 40 परसेंट है ।

सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ । मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से जो चैलेंजेज थे, चाहे कोविड के समय थे, प्रधानमंत्री ग
न्याण अन्न योजना, जो 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को, चाहे 200 करोड़ वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे हेल्थ के लिए लांग
क्चर की मजबूती देने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात हो, रेल, रोड, एनर्जी और कम्युनिकेशन
स हिसाब से बजट का प्रावधान रखा गया है, वह अपने आपमें बहुत अनुकरणीय है । हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
ारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । अंत में मैं यह कह
नी वाणी को विराम देता हूँ:

कुछ तो फूल खिलाये हैं हमने और कुछ फूल खिलाने हैं,

मुश्किल है यह बाग में, अब तक कांटे कई पुराने हैं ।

धन्यवाद ।

RI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairperson, Sir, before I enter into the discussion on General Budget
23-24, I would like to draw the attention of this House to one thing. During his speech, the Leader of the Hou
hon. Prime Minister has mentioned many times about 2014. Whenever he mentions about 2014, I am remind
two crore jobs in every year for our youth. Nine years have passed. More than 18 crore youths should have got
ployment. When he was mentioning about 2014, I was reminded of Rs.15 lakh to every household. Nothing
ppened in this regard. In 2014, he promised that it would be sent to the bank account of every household
reover, he also promised some two/three years back that he will double the income of farmers by 2022. Now, i
23. What has happened? The hon. Prime Minister of India has made all the promises just to pose himself that
l do everything for the people of this country.

But nothing is happening in reality. In the same way, I want to impress upon this House that the Indian p
d middle-class people are suffering a lot. Whether they live in the rural areas or in the urban areas, they
ffering a lot because of price rise, unemployment, and dwindling income.

Actually, day by day, year after year, Budget after Budget, the allocations made for the poor and vulnera
tions are being slashed. Take for instance, MGNREGA. It is a social security scheme, which had been brou
the UPA Government, by the hon. Dr. Manmohan Singh in February, 2005. What had happened at that tim
ores and crores of people living in the villages used to get 100 days job. They used to get 100 days employme
om that employment, they used to earn their every day?s bread and butter at that time. The provision made

NREGA for the year 2023-24 is Rs. 60,000 crore. In 2022-23, it was Rs. 73,000 crore. In the Revised Estimat vas made Rs. 89,400 crore. That means, the number of labour to be paid, the people who had been engaged reased multi-fold because there was an increase of estimates from Rs. 73,000 to Rs. 89,000 crore. But h me, they have reduced the allocation to Rs. 60,000 crore this time? That means, this Government is erested to continue this scheme of the UPA.

Sir, what is happening now? What is the percentage of Rs. 60,000 crore in GDP terms? It is just 0.2 per c the allocations made of Rs. 60,000 crore.

What does the Report prepared by the economists of the World Bank say? They have reported that at lea per cent of the GDP should be provided for the MGNREGA. But are they giving it? No. Even now, t rticular scheme owes a debt of Rs. 15,000 crore. They have provided Rs. 60,000 crore. But there is a balance 15,000 crore this year. If we deduct Rs. 15,000 crore from Rs. 60,000 crore, it comes to only Rs. 45,000 cro in reality, it will not be Rs. 60,000 crore. It will be Rs. 45,000 crore. If we calculate in percentage of G ms, it would get reduced still further from 0.2 per cent. So, is it fair on the part of a Welfare Government? J fore half an hour back, the hon. Prime Minister said that it is a Welfare Government. But is it really a Welf vernment? I want to know it.

Moreover there is a PM-KISAN Scheme, which is intended for the welfare of the farmers. But what ppened? In 2022-23, they had provided Rs. 68,000 crore. Now, they have provided Rs. 60,000 crore. In vised Estimates also, it was Rs. 60,000 crore; and now in the Budget Estimates also, it is Rs. 60,000 crore. T ans, they have not increased the allocation in the Revised Estimates. They have not increased the Bud imates this year. Does that mean all these farmers have become rich overnight? I want to know. How have th come rich? The PM-KISAN scheme is intended for the poor farmers. But have they become industrial ernight? No. They have not become rich. They have not been included in the higher income group. In real ngs are going from bad to worse.

Sir, they are killing schemes after schemes.

They are not interested in helping the poor. The budget allocation made in PM-KISAN, for 2022-23, was 000 crore and still it is Rs. 60,000 crore in 2023-24. The food subsidy has been reduced by Rs. 89,844 cr ereas the fertiliser subsidy has been reduced by Rs. 50,120 crore. The subsidy on petroleum has also be uced to Rs. 6,914 crore. The subsidy on urea has been reduced to Rs. 22,998 crore. If we add these subsid ether, it comes to about Rs. 1,58,996 crore. This is what they have reduced from the originally allocated budg t proper on the part of this Government? I want to know this from the Finance Minister when she will reply. last fiscal year 2022-23, the expenditure cut in education was Rs. 4,397 crores. Last year, the health expendit s reduced by Rs. 9,255 crore. Also in the last year, the allocation for social welfare measures was reduced by 78 crore in the revised estimates. Similarly, the total allocation for educational empowerment for minoriti ich was Rs.2,515 crore in 2022-23, has been reduced to Rs.1,689 crore. As far as the allocation for ru velopment is concerned, the budget allocation for 2023-24 has been reduced from Rs.1,82,382 crore to 9,964 crore. There is a reduction of Rs. 22,418 crore.

Now, I am coming to the Finance Commission?s grants to States. As per the 2022-23, Budget Estimate, th ve provided Rs. 1,92,108 crore to the States. The Revised Estimate was reduced to Rs. 1,73,257 crore. It w ther reduced to Rs. 1,65,418 crore in the Budget Estimate of 2023-24. The States have been facing loss due

s and surcharge, mounting in the recent years, even after the recommendations of the 15th Finance Commiss devolution of 41 per cent of Central taxes to States; the Centre is only giving 30 per cent as of now. The sta s due to this was Rs. 2,12,427 crore in 2020-21 which was further increased to Rs. 2,99,251 crore in Revi imate of 2022-23 and to Rs. 3,56,504 crore in 2023-24 Budget Estimate. Is it cooperative federalism or cohes eralism? I want to know this, Sir. The actual capital expenditure in 2022-23 (BE) was Rs. 7,50,246 crore wh s reduced to Rs. 7,28,274 crore in the Revised Estimate of 2022-23 which is just 2.67 per cent of the GDP. No m coming to the revenues. The implication of revenue loss due to marginal tax rebate amounts to Rs. 38,0 re which is 0.84 per cent only. It is 0.0084 per cent of the total receipts of Rs. 45,03,097 crore for 2023- dget Estimate. The sharp rise in inflation has reduced the real value of money to 50 per cent. They freezed rsonal income tax rates since 2014 at 42 per cent with cess and surcharge, the tax rebates would not have a sitive impact on falling consumption values. Even after so many cuts in infrastructure spending and welf asures to meet the total expenditure of Rs. 41,87,232 crore which is 15.3 per cent of GDP, their net tax revenue 20,86,662 crore only, that is, 7.7 per cent of the GDP. In the absence of disinvestment, they have be rrowing heavily. As per 2022-23 budget, they have borrowed Rs. 17,55,314 crore.

Your interest burden is Rs. 10,79,971 crore. How will this massive rise help to achieve the macro-econon bility? It will not help to achieve growth; it will not help in employment generation; it will not help redu lation; and it will not alleviate the distress of the poor.

Sir, everybody talked about the other issue, that is the ?A issue?. My only question is this. There is one of stern ports in Odisha owned by a company. A sum of Rs. 45,000 crore has been remitted to the account of t rticular company from Mauritius. It has been remitted by three companies with the same address in Mauriti ree companies have sent the money towards a share deposit of the particular company. Who are those particu rsons? From where in Mauritius has the money come? Is there any scrutiny regarding that? The SEBI is sleep er this issue. All the financial issues which are clandestinely happening in India are dwindling the economy o day. This is the most dangerous thing. It has to be taken very seriously.

Some time back, the hon. Leader of the House has mentioned about 2G spectrum. There is no reference o the President?s Address. Why should he refer to 2G? I stood up and asked him this question but he did not answ the people connected to the 2G spectrum were falsely accused. They have come out unscathed with not eve gle charge against them. Then, why should he mention this in his speech? Such a tall and towering personality ming before the Parliament of India and making sweeping remarks against the people both inside and outside rliament. Is it fair on the part of the particular person? ? (*Interruptions*) Through you, I want to know this. Be rime Minister, he should not be muscling on the persons who are of a very good nature. It had gone for judic utiny. For about five years, judicial scrutiny was conducted but nothing was found wrong. The Government co find anything against the persons who were accused. They were unnecessarily put into jail. They were fals used. ? (*Interruptions*)

Sir, now, I want to just mention about a problem. You know pretty well about that problem because y ong to the adjacent State. In Katchatheevu, what is happening? Katchatheevu is a part and parcel of India. It w nded over to the Sri Lanka which has got no jurisdiction at all in Katchatheevu. But unfortunately, because of ecutive agreement between India and Sri Lanka, at the time of emergency, it had happened. It has not be nceded by the Indian Constitution. Had there been any such provision, it would have been conceded by the Ind

nstitution and both the Houses would have passed the resolution and the Constitution amendment would ha
ppened regarding this.

But because of the Katchatheevu issue, all our fishermen are suffering in the hands of the Sri Lankan secu
ces day in day out. They are arresting our people. They are taking out all the proceeds which the fishern
lected from the sea. They have been taken into custody, and they are put into the jail. Not only the persons suf
also their boats have been seized and kept in the open sun. They are not returning the boats. This is the day-
affair of the fishermen. That is why, I request the Government of India that at least now they should wake
see that there is a proper agreement. If at all any ceding should be done, it should be done by the Parliament
ia. Now it is against the parliamentary system; it is against the Parliament. I think the people concerned sho
e note of this, and we should get back the Katchatheevu. Then only the things will be all right as per
nstitution.

Sir, the 13A amendment of the Sri Lankan Constitution has not been considered so far by the Sri Lank
vernment. The 13A amendment goes to show land power of the North and North-East Province of Sri Lanka, a
s also provides the police power; the police power should be vested with the North and North-East Provinc
ministration. The 13A amendment was loudly spoken by many Prime Ministers but so far nothing is happenin
e 13A amendment has not been implemented so far by the Sri Lankan Government. The mighty Government
ia should go before the Sri Lankan counterpart and see that 13A is implemented.

Sethusamudram is one of the most important projects. It is a project of Rs.2400 crore. The work had be
ugurated by the then hon. Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, in the immediate presence of So
ndhi Ji and my leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi. ? (*Interruptions*)

57 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, I will conclude soon. I would not take much time. I know you have come only for the purpose of ?* me

The deep-sea work had started at particular second, at the stroke of inauguration itself. While the work w
ng on in Adam?s Bridge in 2007, on 14.9.2007, the court had ordered to stay the project. The claim of
itioner was that the project would damage the mythological Ramar Bridge and its heritage. But what
ppened now? Recently, in Rajya Sabha, the Minister himself has narrated that this particular so-called Ra
dge has nothing to do with that. He has said that it has got no man-made structure. On 8.5.2007, as a Ministe
d in the Lok Sabha that the Adam?s Bridge area was made up of sand shoals and limestone caused by natu
ves and sedimentation over a period of 5-7 lakh years. ? (*Interruptions*)

According to the geological studies by GSI, there is no evidence of man-made structure of heritage val
w, after 15 years, the Minister for Science and Technology has stated this in the Rajya Sabha on 22.12.22. T
ne facts have been reiterated by Dr. Jitendra Singh. I am happy at least now the Government of India is sensiti
understand what is the scientific temperament behind this. This scientific temperament has to prevail over t
ue and it should see that the Sethusamudram project is immediately started forthwith without any hesitati
ank you very much, Sir.

00hrs

RI DAYANIDHI MARAN : Sir, I have a Point of Order. *....(Interruptions)* There is no quorum.

ON. SPEAKER: What is the Point of Order?

RI DAYANIDHI MARAN: There is no quorum, Sir. *....(Interruptions)* It is the Ruling Party. It is their Budg t there is no quorum. *....(Interruptions)* Look at the benches. All benches are empty. *....(Interruptions)*

Hon. Speaker, Sir, since you are there, it is my duty to bring it to your notice. The Ruling Party, the BJP l ed itself. *....(Interruptions)*

RI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): When an hon. Member demands for quorum, then the quorum bell sho rung.

ON. SPEAKER: Okay. बेल बजाइए ।

? (*Interruptions*)

ननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है

04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday,February *9, 2023/Magha 20, 1944 (Saka).*

-

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament f India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live lecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of e House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

---

ot recorded.

Not recorded.

ot recorded.

ot recorded.

ot recorded.

ot recorded.

Expunged as ordered by the Chair.

Expunged as ordered by the Chair.

Expunged as ordered by the Chair.

ot recorded.

..* English translation of this part of the Speech originally delivered in Bengali.

ot recorded.